

गरीबी उन्मूलन लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के **मुख्यमंत्री** ने तीन साल के भीतर राज्य में **गरीबी उन्मूलन** की योजना की घोषणा की है। उन्होंने सभी के लिये आवास, पानी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

मुख्य बटु

■ गरीबी के बारे में:

- गरीबी एक ऐसी स्थिति या अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास **न्यूनतम जीवन स्तर** के लिये वित्तीय संसाधन और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। गरीबी का मतलब है कि रोजगार से आय का स्तर इतना कम है कि बुनियादी मानवीय जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं।
- **वशिव बैंक के अनुसार**, गरीबी का अर्थ है खुशहाली में कमी और इसमें कई आयाम शामिल हैं। इसमें कम आय और गरमि के साथ जीने के लिये आवश्यक बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में असमर्थता शामिल है। गरीबी में स्वास्थ्य और शिक्षा का निम्न स्तर, स्वच्छ जल और स्वच्छता तक खराब पहुँच, अपर्याप्त शारीरिक सुरक्षा, आवाज़ की कमी और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिये अपर्याप्त क्षमता और अवसर भी शामिल हैं।
- वर्ष 2018 में, दुनिया के लगभग 8% श्रमिक और उनके परिवार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन **1.90 अमेरिकी डॉलर (अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा)** से कम पर जीवन यापन कर रहे थे।

■ गरीबी के प्रकार:

- **पूर्ण गरीबी:** ऐसी स्थिति जिसमें घरेलू आय बुनियादी जीवन स्तर (भोजन, आश्रय, आवास) को बनाए रखने के लिये आवश्यक स्तर से कम हो। यह स्थिति विभिन्न देशों के बीच और समय के साथ तुलना करना संभव बनाती है।
 - इसे पहली बार वर्ष 1990 में पेश किया गया था, "एक डॉलर प्रतिदिन" गरीबी रेखा ने दुनिया के सबसे गरीब देशों के मानकों के अनुसार पूर्ण गरीबी को मापा। अक्टूबर 2015 में, वशिव बैंक ने इसे \$1.90 प्रतिदिन पर निर्धारित कर दिया।
- **सापेक्ष गरीबी:** इसे सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है, अर्थात आसपास रहने वाली आबादी के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर। इसलिये यह आय असमानता का एक उपाय है।
- आमतौर पर सापेक्ष गरीबी को जनसंख्या के उस प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, जिसकी आय औसत आय के एक निश्चित अनुपात से कम होती है।

■ भारत में गरीबी का अनुमान

- भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI)** के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा एकत्र आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है।
- **अलघ समिति (1979)** ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक वयस्क के लिये क्रमशः 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित की।
- इसके बाद विभिन्न समितियाँ; **लकड़ावाला समिति (1993)**, **तेंदुलकर समिति (2009)**, **रंगराजन समिति (2012)** ने गरीबी का आकलन किया।
- रंगराजन समिति की रिपोर्ट (2014) के अनुसार, **गरीबी रेखा का अनुमान शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में लगाया गया है।**